वर्ष : 03– अंक : 27 – जून 2025

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

निष्क्रिय पैक्स में जान फूंकने की तैयारी

12 ऑपरेशन सिंदूरः घुटने पर आया पाकिस्तान

18 देश को हर क्षेत्र में विकसित और सुरक्षित कर रही मोदी सरकार

अनुक्रमणिका

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

जून 2025, अंक 27, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला

संपादक
रोहित कुमार

सह संपादक
अँक अँजलीदीप

सदस्य
माधवी एम. विप्रदास
विवेक सक्सेना
हितेंद्र प्रताप सिंह
राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017
इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

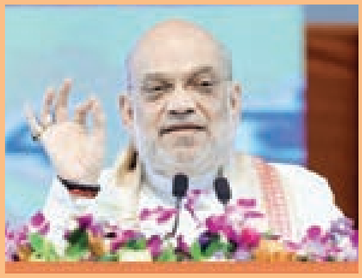

निष्क्रिय पैक्स में जान फूंकने की तैयारी

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारिता की बुनियाद मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में व्यापक सुधार किया जा रहा है।

आवरण कथा

पेज 06 देखें

पेज 12 देखें

ऑपरेशन सिंदूरः घुटने पर आया पाकिस्तान

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर उसे घुटने पर ला दिया।

पेज 22 देखें

प्रवासी भारतीयों को घर लौटने में नहीं होगी कोई असुविधा

पेज 23 देखें

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली इंजन हैं सहकारी समितियां

पेज 24 देखें

इफको ने उतारा नैनो जिंक और नैनो कॉपर

पेज 27 देखें

राष्ट्रीय-आर्थिक विकास में सहकारिता की अहम भूमिका

पेज 14 देखें

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही सरकार

भारत का युवा अपने परिश्रम और नवाचारों से दुनिया को दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार-स्वरोजगार के अवसर बढ़ें।

पेज 15 देखें

पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही होगी

पेज 16 देखें

भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए तैयार

पेज 20 देखें

गरीब के घर के पास ही सुलभ होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

पैक्स में सुधार से मजबूत होती सहकारिता

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को सशक्त करने के लिए सरकार ने कई अहम उपाय किए हैं। केंद्र सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल सहकारिता क्षेत्र की निचली इकाई पैक्स से लेकर अपेक्स तक को मजबूत बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के तहत मॉडल कानून बनाकर राज्यों को भेजा गया, जिसे सभी राज्यों ने हाथोहाथ अपना लिया। इसके बाद पैक्स की कारोबारी गतिविधियां मजबूत बनाने के लिए सरकार ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की कई योजनाओं का लाभ उन्हें देने का फैसला किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रालय द्वारा अल्प समय में सहकारी क्षेत्र को सशक्त और जीवंत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल एवं ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई। आज जब विश्व भर में 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' को पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, भारत का सहकारी तंत्र भी तेजी से मजबूत हो रहा है। देशभर में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) का सशक्त प्रसार हो रहा है, जो अब ग्रामीण भारत में 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

पैक्स के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के क्रम में मंत्रालय ने पैक्स के उपनियमों में बदलाव कर उन्हें बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 63,000 पैक्स का कंप्युटरीकरण अंतिम चरण में है। एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सहकारिता मंत्रालय ने 'विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम' आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब पैक्स केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे गोदाम संचालन, डेयरी गतिविधियों, बीज वितरण और ई-मार्केटिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है।

पैक्स आज ग्रामीण विकास की रीढ़ बन चुकी है। इनके सशक्तीकरण से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, बल्कि मौसमी बेरोजगारी में भी कमी आने की उम्मीद है। इससे करीब 13 करोड़ किसानों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन के अवसर प्राप्त होंगे। सहकारी समितियों को अधिक समावेशी बनाने हेतु महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे सामाजिक समरसता को बल मिल रहा है और नेतृत्व विकास की प्रक्रिया भी सशक्त हो रही है।

पैक्स में हो रहे यह सुधार भारतीय सहकारिता को आधुनिकता, कार्य दक्षता और पारदर्शिता से जोड़ रहे हैं, जिससे किसानों का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। निःसंदेह, प्रगति के इस क्रम में सहकारी समितियां ग्रामीण समृद्धि के एक सशक्त वाहक के रूप में स्थापित होंगी।

'सहकार उदय' पत्रिका के इस अंक में 'पैक्स में सुधार से मजबूत होती सहकारिता' विषय पर सारगर्भित लेखों के साथ-साथ अन्य उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत की गई है। हमें विश्वास है कि यह अंक आपके लिए उपयोगी, प्रेरक और जानकारी से परिपूर्ण सिद्ध होगा।

सादर धन्यवाद — **जय सहकार**

देश की जनता से हमारा वादा है- भारत का समग्र विकास। आज हम जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं और जो निर्णय ले रहे हैं, वे देश के एक हजार साल का भविष्य लिखने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मोदी सरकार में सहकारिता गरीबों, वंचितों व किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। सरकार हर देशवासी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारत में सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में सहकारी संगठनों के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते एनसीडीसी पूरे भारत में पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन और कई सहकारी संगठनों में सहकारी भावना को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

श्री मुरलीधर मोहोल,
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारी समितियों को यह सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिले।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

इफको नैनो उर्वरक जैसे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी किसानों के लिए क्रांतिकारी उर्वरक साबित हो रहे हैं। यह न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

सहकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में सहकारी समितियां ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बन रही हैं। तकनीकी नवाचार, वित्तीय समावेशन और बाजार तक सीधी पहुंच जैसी पहलों ने किसानों और ग्रामीण समुदायों को नई पहचान दी है।

सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

वर्ष 2024-25 का तृतीय अग्रिम अनुमान

खाद्यान्न उत्पादन का बना नया रिकॉर्ड

➲ देश का खाद्यान्न उत्पादन पहली बार 35.40 करोड़ टन पार पहुंचा। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन उत्पादन ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड

सहकार उदय टीम

कृषि एवं किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार के केंद्र में रहा है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, राज्य सरकारों के सहयोग, किसानों की अथक मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता से देश में खाद्यान्न के भंडार भर गए है। पिछले वर्ष बेहतर मानसून ने भी फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फसल वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर पहली बार 35.40 करोड़ टन पर पहुंच गया है। यह 2023-24 के 33.23 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन से 2.17 करोड़ टन अधिक (6.5% की वृद्धि) है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 का तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। चालू फसल वर्ष में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

इस दौरान धान का उत्पादन 1490.74 लाख टन (रिकॉर्ड), गेहूं का 1175.07 लाख टन (रिकॉर्ड), मक्का का 422.81 लाख टन (रिकॉर्ड), श्रीअन्न का 180.15 लाख टन, तूर का 35.61 लाख टन और चना का उत्पादन 113.37 लाख टन रहा है। तिलहन फसलों का 426.09 लाख टन उत्पादन हुआ है, जिसमें मूंगफली 118.96 लाख टन (रिकॉर्ड), सोयाबीन 151.80 लाख टन (रिकॉर्ड), रेपसीड-सरसों का 126.06 लाख टन उत्पादन हुआ है। इसी तरह, दलहन उत्पादन 252.38 लाख टन हुआ है, जो पिछले वर्ष के 242.46 लाख टन उत्पादन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। दलहन फसलों में मूंग उत्पादन 38.19 लाख टन रहा है, जो पिछले वर्ष के 31.03 लाख टन से 7.16 लाख टन अधिक है। तूर (अरहर) उत्पादन 35.61 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 34.17 लाख टन से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाकर किसानों की आमदनी को बढ़ाने का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना हो, ड्रॉप-मोर क्रॉप हो, मैकेनाइजेशन की योजना हो, सस्ती खाद हो या फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसी योजना हो या अन्य, इन सबके परिणाम हमारे सामने है। सरकार के प्रयासों से खाद्यान्न उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलहन व तिलहन का उत्पादन और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान तनावपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में भारत के पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक होने से उसकी स्थितियां और मजबूत होंगी। देश के गोदाम अनाजों से लबालब भरे पड़े हैं। किसानों के पास भी अनाज अटा पड़ा है। इससे घरेलू कमोडिटी बाजारों में महंगाई पैर नहीं पसार पाएगी। आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि निर्यात से वैश्विक स्तर पर अपनी पोजिशन मजबूत करने में मदद मिलेगी।

खरीफ फसलों का बढ़ा एमएसपी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का एमएसपी बढ़ाकर 2389 रुपए (ए ग्रेड) और 2369 रुपए (सामान्य) प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपए प्रति क्विंटल) के लिए की गई है। इसके बाद रागी (596 रुपए प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपए प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपए प्रति क्विंटल) के एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। ■

प्रमुख फसलों का एमएसपी

अनाज	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)	
	वर्ष 2025-26	वर्ष 2024-25
धान (ग्रेड ए)	2389	2320
धान (सामान्य)	2369	2300
मक्का	2400	2225
तूर (अरहर)	8000	7550
मूंग	8768	8682
उड़द	7800	7400
ज्वार (हाइब्रिड)	3699	3371
ज्वार (मालदंडी)	3749	3421
बाजरा	2775	2625
रागी	4886	4290
मूंगफली	7263	6783
सूरजमुखी के बीज	7721	7280
सोयाबीन (पीला)	5328	4892

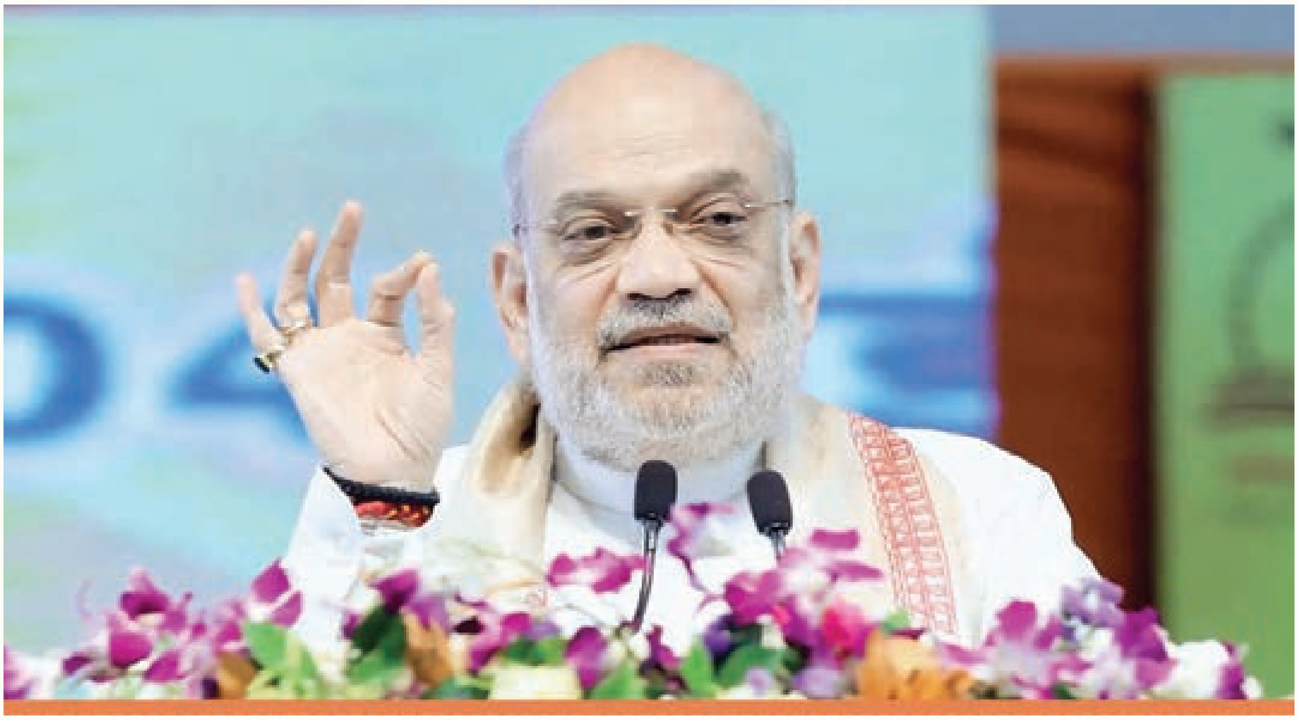

निष्क्रिय पैक्स में जान फूंकने की तैयारी

सहकार उदय टीम

- लिक्विडेशन में गए पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए आएगी नई नीति : श्री अमित शाह
- कानूनी सुधार के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय राज्यों को जारी करेगा एडवाइजरी
- प्रक्रियागत कानूनी दिक्कतों को दूर कर निष्क्रिय पैक्स को किया जाएगा सक्रिय
- सक्रिय नहीं किए जा सकने वाले पैक्स का पंजीकरण रद्द कर बनाया जाएगा नया पैक्स

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारिता की बुनियाद मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में व्यापक सुधार किया जा रहा है। इसके तहत पैक्स का कंप्युटरीकरण करने सहित उसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब निष्क्रिय पैक्स में जान फूंकने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कानूनी सुधार किए जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में

बताया कि सरकार जल्द ही लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए नीति लेकर आने वाली है।

सहकारिता से सबको जोड़ने और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होंगे तब तक सहकारी ढांचा मजबूत नहीं हो सकता है। '*सहकार से समृद्धि*' के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2029 तक देश की हर उस पंचायत में पैक्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है जहां अभी यह नहीं है। इसके तहत पांच वर्ष में 2 लाख नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाई जानी है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, 15 फरवरी, 2023 से लेकर 25 अप्रैल, 2025 तक कुल 19,619 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक (पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन) समितियां बनाई जा चुकी हैं। इन एमपैक्स में पैक्स, लैम्प्स (लॉन्ग एरिया मल्टी परपज सोसाइटी) और एफएसएस (फारमर्स सर्विस सोसाइटी) समितियां शामिल हैं। जबकि पहले से मौजूद पैक्स की संख्या करीब 1.05 लाख है। इनमें से 35 हजार से ज्यादा पैक्स विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हैं। इनमें से कुछ लिक्विडेशन में हैं तो कुछ अन्य कारणों से निष्क्रिय हैं जिन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, देश में इस समय कुल 8,43,099 सहकारी समितियां हैं। इनमें से प्राथमिक समितियां 8,39,244 हैं जिनमें सक्रिय समितियों की संख्या 6,44,608 हैं। 1,48,329 सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं और 46,307 समितियां लिक्विडेशन में हैं।

कानूनी सुधार से सुधरेगी कम सक्रिय पैक्स की सेहत

निष्क्रिय पैक्स में सबसे पहले उनकी पहचान की जा रही है जो चार-पांच साल से निष्क्रिय हैं और उन्हें सक्रिय किए जाने की संभावना मौजूद है। इसके लिए उनकी प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर कर उन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा। दूसरा, ऐसे पैक्स जो 10-20 साल से निष्क्रिय हैं और लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हैं, उनके लिए कानूनी सुधार की संभावना तलाशी जा रही है ताकि इसके माध्यम से उनका पंजीकरण रद्द कर उन पंचायतों में नई पैक्स का गठन किया जा सके। चूंकि पैक्स राज्यों का विषय है और उन्हीं के कानून से संचालित होते हैं जिनमें एकरूपता नहीं होने से कई तरह की चुनौतियां पेश आती हैं। कई राज्यों में कानूनी सुधार न होने से पैक्स या तो निष्क्रिय हैं अथवा पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए कानूनी सुधार की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। राज्यों की सहमति से पैक्स की प्रक्रियागत खामियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय दिशा-निर्देश तैयार करेगा और राज्यों को एडवाइजरी भेजेगा। उस एडवाइजरी पर अमल कर राज्य कानून में सुधार करेंगे और उसके माध्यम से निष्क्रिय पैक्स को सक्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

इस दिशा-निर्देश में लिक्विडेशन में गई पैक्स को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत देने के प्रावधान किए जाएंगे और सरल कानून बनाने के सुझाव दिए जाएंगे। इसके अलावा इस तरह के प्रावधान किए जाने की भी संभावना है ताकि आगे चलकर वे किसी और कानूनी पचड़ों में न पड़ सकें और आसानी से काम करते रहें। पैक्स में व्यापक सुधार और उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पहले नए मॉडल बायलॉज बनाए जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लागू कर दिया है। अब कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर मंत्रालय का जोर है। सहकारिता मंत्रालय सुप्तावस्था में पड़े पैक्स को सक्रिय करने के लिए राज्यों को लगातार प्रोत्साहित करता रहा है, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से ऐसा करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए ही अब कानूनी सुधार पर फोकस किया जा रहा है।

पैक्स से अपैक्स तक ढांचागत सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने 'पैक्स से अपैक्स' तक ढांचागत सुधार का जो बिगुल फूंका है, उसकी वजह से भारतीय सहकारिता आंदोलन की गति तेज हो गई है। श्री शाह के प्रयासों से पैक्स के लिए नया मॉडल बायलॉज बनाया गया जिसके तहत पैक्स को 22 से ज्यादा कारोबार करने की मंजूरी दी गई। इनमें पेट्रोल पंप खोलने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनने, जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने, पीएम अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने और उनका संचालन करने जैसे कारोबार की अनुमति मिली है। पैक्स का कारोबारी दायरा लगातार बढ़ रहा है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के कारगर प्रयास के नतीजे अब स्पष्ट रूप दिखने लगे हैं।

सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से 60 से अधिक अहम पहल की गई हैं। ग्रामीण स्तर पर सक्रिय पैक्स के कामकाज को पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए मॉडल बायलॉज तैयार कर राज्यों को भेजा, जिसे सभी राज्यों ने अपना लिया। इसके साथ ही पैक्स के विकास के सारे रास्ते खुल गए। पैक्स को आधुनिक बनाने के लिए सभी सक्रिय पैक्स का कंप्युटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,516 करोड़ रुपए है जिसका 60 प्रतिशत (1528 करोड़ रुपए) हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत (736 करोड़ रुपए) राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों की हिस्सेदारी होगी। बाकी 10 प्रतिशत (252 करोड़ रुपए) का खर्च नाबार्ड उठाएगा। नाबार्ड ही इस परियोजना की नोडल एजेंसी है।

47 हजार पैक्स हुए ऑनबोर्ड

पैक्स से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां

- बीज, फर्टिलाइजर और कीटनाशक वितरण
- रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल डीलरशिप
- कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र
- खाद्यान्न खरीद, भंडारण (गोदाम व कोल्ड स्टोरेज) और कृषि उत्पादों की पैकेजिंग
- उचित मूल्य की राशन दुकानें
- मत्स्य पालन, डेयरी और पॉल्ट्री उद्योग
- फार्म मशीनरी कस्टम हायर सेंटर
- बागवानी उत्पादों की खेती
- मधुमक्खी, भेड़, बकरी व सूअर पालन
- रेशम उत्पादन
- सामुदायिक सेवा केंद्र, ब्रांडिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां
- बीमा सुविधा, बैंक मित्र व व्यावसायिक प्रतिनिधि
- हर घर नल से जल सेवा (जल जीवन मिशन)
- गोबर गैस
- बिजली बिल वितरण और कलेक्शन सेंटर
- लॉकर सुविधा

परियोजना के तहत 67,930 पैक्स को कंप्युटरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 46,920 पैक्स नाबार्ड के कॉमन सॉफ्टवेयर से जुड़कर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र (9,906) के पैक्स की है। इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के पैक्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं। बाकी पैक्स का कंप्युटरीकरण अपने अंतिम चरण में है। आज देश के कई राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक कंप्यूटर नेटवर्क के कारण नाबार्ड से जुड़ गए हैं। सरकार ने पैक्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो किसानों के लिए उनकी भाषा में बैंक खाता खोलने का काम करेगा। देशभर में कंप्युटरीकृत पैक्स हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल और असमिया समेत भारत की 11 मुख्य भाषाओं में काम कर रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आई है।

पैक्स के कंप्युटरीकरण और इंटरनेट से जुड़ जाने से उसके सारे कामकाज ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे पैक्स के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में मदद मिल रही है। ऑनलाइन हो जाने और नाबार्ड के एकल सॉफ्टवेयर से जुड़ जाने के बाद कई तरह की अन्य सेवाएं पैक्स से सीधे जुड़ गई हैं, जिससे पैक्स के कारोबार का दायरा बढ़ रहा है और सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में कई तरह के सुधार हो रहे हैं। नाबार्ड में पैक्स की डिजिटल पहुंच हो गई है और पैक्स के वित्तीय लेनदेन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभव हो गई है। सहकारिता की निचली इकाई से लेकर शीर्ष इकाइयां तक एक दूसरे से परस्पर जुड़ रही हैं जिससे सहकारी समितियों के सदस्यों को सीधा लाभ मिलने लगा है।

मॉडल बायलॉज से बढ़ी पारदर्शिता

पैक्स की मजबूती के लिए प्रबंधन संबंधी भी सुधार किए गए हैं। मॉडल बायलॉज के माध्यम से पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आने लगी है। इसमें सदस्यों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इनके बोर्ड में महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। पैक्स के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसमें पेशेवरों को रखने की छूट दी गई है। सहकारिता का लाभ ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पैक्स में भूमिहीन किसान, खेतिहर श्रमिक प्रतिनिधि, पशुपालक, डेयरी किसान, मत्स्य पालक को सदस्य बनाया जा सकता है। पैक्स में किसी को सदस्यता देने से मना नहीं किया जा सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के सदस्यों को सदस्यता देने के प्रावधान को भी सरल बना दिया गया है।

श्री शाह का कहना है, 'पैक्स को सशक्त करने और उसके आर्थिक उन्नयन से ही सहकारी आंदोलन को गति मिलेगी। मॉडल बायलॉज लागू हो जाने से पैक्स के कामकाज का दायरा बढ़ेगा जो उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा।' सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स के बायलॉज में एकरूपता आ गई है, जिससे केंद्र, राज्य, जिला व ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली सहकारी संस्थाओं को सहूलियत हो रही है।

मॉडल बायलॉज लागू होने से पैक्स को मल्टी परपज बनाने का विकल्प मिल गया है। इससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। मॉडल बायलॉज को लागू करने से पैक्स को विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार, पैक्स की सूची में तकरीबन 80 ऐसे क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिनमें पैक्स अपना कामकाज बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार का उद्देश्य पैक्स को मल्टी परपज बनाकर लाभ कमाने वाली समिति बनाना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी हैं और उनका रुझान सहकारिता की ओर होने लगा है।

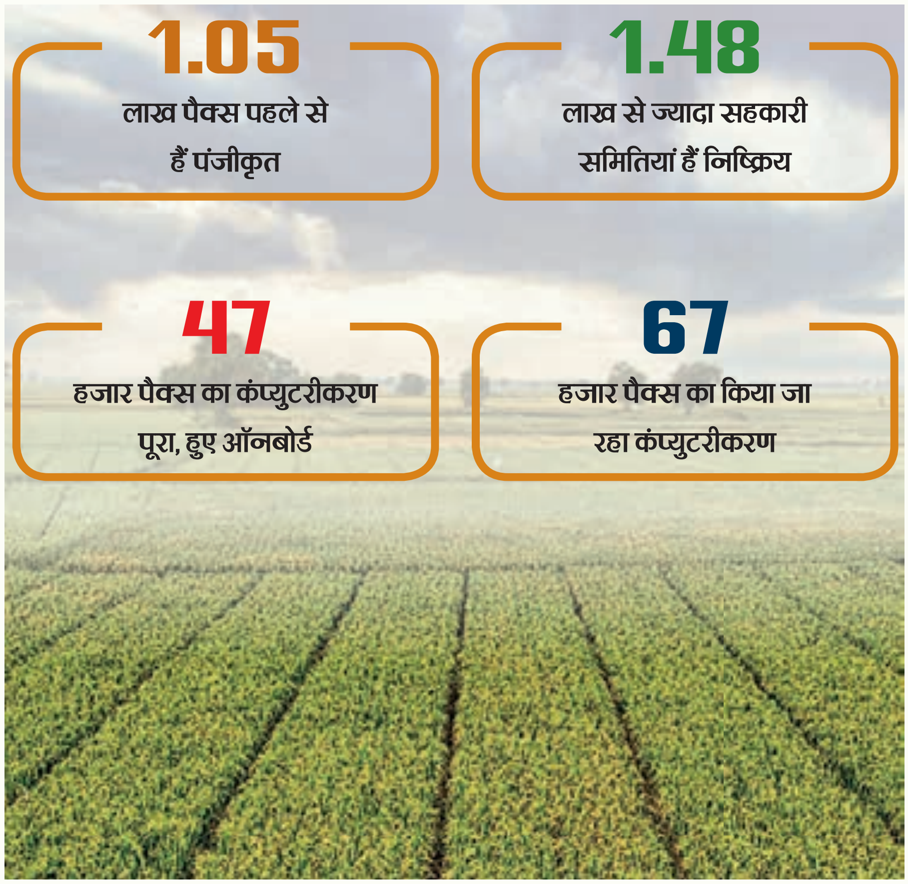

पैक्स के कई रूप

सहकारी आंदोलन की पहली कड़ी पैक्स की परिकल्पना बहुत पहले ही भारत में कर ली गई थी। असम व छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों और दूर-दूर बसे गांवों को जोड़कर बनाए गए पैक्स को लॉन्ग एरिया मल्टी परपज सोसाइटी (लैंप्स) के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में फारमर्स सर्विस सोसाइटी (एफएसएस) के नाम से भी सहकारी समितियां कार्य करती हैं। देश में सौ साल पुराने पैक्स भी हैं। स्थानीय स्तर पर अल्पकालिक कार्य के लिए इस तरह की समितियां बनी। इसके तहत समिति से सदस्यों को खेती की जरूरतें, शादी, बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य छोटे बड़े कार्यों के लिए आसानी से ऋण मिल जाता है। बैंक न होने के बावजूद पैक्स अपने सदस्यों की जरूरतों को बैंक जैसी सेवाएं देती हैं। सहकारी समिति में सदस्यों के बचत वाला धन एक दूसरे की जरूरतों के लिए जमा होता है। वही इसकी पूंजी होती है, जिससे सदस्यों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। दरअसल, सभी पैक्स जिला सेंट्रल सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के सदस्य होते हैं। पैक्स यहां से ऋण लेकर भी अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जबकि डीसीसीबी लाइसेंसयुक्त बैंक हैं, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से राज्य सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारें तीन स्तरीय सहकारी संस्थाओं की प्रशासक हैं जो राज्यों के सहकारी कानून से संचालित होते हैं। नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को रिफाइनेंस और सपोर्ट करता है। कंप्युटरीकरण हो जाने के बाद पैक्स अपने डीसीसीबी और राज्य सरकारी बैंकों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। ■

'विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका' पर जोर देकर बोले श्री अमित शाह

नए पैक्स के लिए भी बनेगी सहकारी नीति

सहकार उदय टीम

- सहकारिता क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लाभ जब तक पैक्स और किसानों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता
- केंद्र सरकार कम सक्रीय प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को सक्रिय बनाने में राज्यों के साथ मिलकर करेगी प्रयास
- सभी को जागरूक करके पारदर्शिता के नए आयाम तय करने और सहकारी ढांचे को मजबूत करने पर जोर
- सहकारिता वर्ष के दौरान 'साइंस ऑफ कोऑपरेशन' और 'साइंस इन कोऑपरेशन' को उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सहकारिता आंदोलन को नए आयाम के साथ दिशा और विस्तार देने का बहुत बड़ा प्रयास शुरू हुआ है। वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही '*सहकार से समृद्धि*' और 'विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका' के विजन के साथ देश में सहकारी विकास को नई गति मिल रही है। इन तथ्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में राज्य सहकारी संघ द्वारा 'विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका' विषय पर आयोजित महासम्मेलन में साझा किया। उन्होंने कहा कि जबतक सहकारिता क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का लाभ निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और किसानों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता। श्री शाह ने इसके लिए सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने और पैक्स को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में जागरूकता, प्रशिक्षण और पारदर्शिता लाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए मोदी सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत दो लाख नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियां रजिस्टर्ड की जाएंगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने विभिन्न प्रकार की करीब

25 आर्थिक गतिविधियों में पैक्स का विस्तार किया है। उन्होंने पैक्स की सामर्थ्य बढ़ाने वाला एक बड़ा नीतिगत ऐलान करते हुए कहा कि भारत सरकार जल्द ही लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए भी नीति ले कर आने वाली है।

सभी राज्यों और जिलों तक सहकारिता का विस्तार हो

श्री शाह ने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि सहकारी आंदोलन के तहत हर राज्य और जिले तक सहकारिता का विस्तार हो। इसके साथ ही, हर राज्य में पैक्स की स्थिति सुधरे, जिला स्तरीय संस्थाएं मजबूत हों और उनके माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का सहकारी ढांचा भी मजबूत बने। श्री शाह ने कहा कि कई वर्षों से चली आ रही वैश्विक त्रि-स्तरीय सहकारिता ढांचे की कल्पना में हमने चौथे स्तर को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के ढांचे की हर सहकारी गतिविधि से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों, राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाओं, जिलास्तरीय संस्थाओं और हर क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करते हुए पूरे देश में सहकारिता को पहुंचाना जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि यह पूरा अभियान तीन स्तंभों पर आधारित है - सहकारिता को शासन के मुख्य प्रवाह का हिस्सा बनाना, सहकारिता आंदोलन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता और प्रमाणिकता लाना और अधिक से अधिक नागरिकों को सहकारिता आंदोलन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को गति देना। इन तीनों स्तंभों के आधार पर सहकारिता वर्ष के दौरान कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अब तक अनेक प्रकार के लगभग 57 पहल किए गए हैं। उन्होंने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' के अवसर का उपयोग करने पर जोर दिया।

सहकारी ढांचे को मजबूत करने पर जोर

श्री शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सभी लोगों को जागरूक करने, पारदर्शिता के नए आयाम तय करने और भर्तियों के माध्यम से सहकारी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता शब्द पूरे विश्व में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वर्ष 1900 में था। आजादी के आंदोलन के समय देश में शुरू हुआ सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे देश के एक बड़े भाग में लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन, अब स्थिति बदल चुकी है और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में अनेक प्रकार की नई पहलों को तेज किया जा रहा है। मोदी सरकार ने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। श्री शाह ने कहा कि देश के हर राज्य में सहकारिता से जुड़े सभी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव को मूल संकल्पनाओं के साथ पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है। ■

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान 'साइंस ऑफ कोऑपरेशन' और 'साइंस इन कोऑपरेशन' पर बल दिया है। श्री शाह ने कहा कि हमें गुजरात सहित पूरे देश में 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' के प्रयोग को प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, जिससे सभी सहकारी संस्थाओं का पूरा कामकाज सहकारी संस्थाओं के साथ ही हो। सभी प्राथमिक सहकारी समितियों, डेयरी आदि का बैंक अकाउंट ज़िला सहकारी बैंक में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सभी सहकारी संस्थाओ के बीच सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रयास को गति देनी चाहिए।

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

ऑपरेशन सिंदूर
घुटने पर आया पाकिस्तान

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आतंक पर प्रहार से भारत का दुनिया में बजा डंका
- असरदार कूटनीति, कारगर रणनीति और सेना के अदम्य साहस से तहस नहस हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने
- सिंदूर की शक्ति क्या होती है यह पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ने देखी

सहकार उदय टीम

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर उसे घुटने पर ला दिया। भारत के सटीक हमलों ने तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल और मंत्रालयों एवं सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को प्रदर्शित किया है।

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए भारत ने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं। वह हर आतंकवादी वारदात का मुंहतोड़ जवाब देगा। तीन दिन के अल्पकालिक युद्ध में ही पाकिस्तान त्राहि-त्राहि करने लगा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए उसके इरादों को धूल चटा दिया। जो आतंकवादी कभी पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, उन्हें भारत की सेना ने एक ही निर्णायक कार्रवाई में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठान मिनटों में नष्ट कर दिए गए। भारत का प्रहार इतना जोरदार था कि पाकिस्तान सीजफायर की गुहार लगाने लगा। उसकी गुहार पर भारत ने अपनी शर्तों पर सैन्य कार्रवाई रोकी, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों ने अपना शौर्य दिखाना भी शुरू नहीं किया था। भारतीय सेना ने सीमा पार तक नहीं किया और नौसेना के जहाजों ने एक भी गोला नहीं उगला था। भारत जमीन, आसमान और समुद्र में कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा 'यह नया भारत है- अपार शक्ति और गतिशीलता वाला भारत। आतंक के साजिशकताओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते।' आपरेशन सिंदूर की सफलता के तत्काल बाद अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा 'अब जब मैं एक बार फिर से बिहार में आया हूं, तो उस प्रतिज्ञा को पूरा कर चुका हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न तो रुकी है और न ही धीमी हुई है। अगर आतंकवाद फिर से अपना सिर उठाता है, तो भारत उसे उसके छिपने के स्थान से बाहर निकालेगा और निर्णायक रूप से कुचल देगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत की लड़ाई देश के हर दुश्मन के खिलाफ है, चाहे वे सीमा पार से हों या देश के अंदर।'

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा असाधारण सैन्य पराक्रम

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ द्वारा दिखाए गए असाधारण पराक्रम और अदम्य साहस पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया ने उनकी अद्वितीय बहादुरी देखी है। भारत की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान सुरक्षा की अटूट ढाल हैं, जिनका सबसे पहला कर्तव्य भारत माता की रक्षा करना है। उन्होंने बिहार के वीर सपूत के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए सीमा पर अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर श्री इम्तियाज को भी श्रद्धांजलि दी।

इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने दुनियाभर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है।'

> पूरी दुनिया को सिंदूर का महत्व पता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिलिटरी स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि सिंदूर का क्या महत्व है। प्रधानमंत्री ने आतंकियों के घर में घुसकर उनके हेडक्वार्टर को नष्ट कर भारत की मातृशक्ति का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा करने का काम किया है।
>
> **- श्री अमित शाह**
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की गति, गहराई और स्पष्टता की सराहना करते हुए एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया को सिंदूर का महत्व पता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिलिटरी स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि सिंदूर का क्या महत्व है। प्रधानमंत्री ने आतंकियों के घर में घुसकर उनके हेडक्वार्टर को नष्ट कर भारत की मातृशक्ति का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा करने का काम किया है।

देश की सीमा की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले के जवाब में हमारे रिहायशी इलाके पर हमला किया तब जम्मू फ्रंटियर में लगभग 118 से अधिक पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह करने और नुकसान पहुंचाने का काम बीएसएफ के जवानों ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बहादुरी तभी देखने को मिलती है जब देश पर गर्व, दिल में देशभक्ति की भावना और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है।

बीएसएफ जवानों का समर्पण, शौर्य, पराक्रम और बलिदान आज देश के हर बच्चे की जुबान पर है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों की सजगता के कारण ही कोई भी आक्रमण सीधा देश की सीमा के अंदर क्षति नहीं पहुंचा पाता।■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही सरकार

- विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय युवा

सहकार उदय टीम

भारत का युवा अपने परिश्रम और नवाचारों से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार-स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। इन तथ्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए चयनित हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मौके पर साझा किया। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इनके माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और नवाचार के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। यूपीआई, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) और जीइएम सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों की सफलता यह दिखाती है कि भारत के युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन्स भारत में हो रहे हैं और इसका श्रेय युवाओं को ही है। युवाओं को उनके नए दायित्वों और देश की सेवा के प्रति सचेत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तथा देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाना भी हम सब का दायित्व है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा।

मैन्यूफैक्चरिंग मिशन से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

केंद्रीय बजट में मैन्यूफैक्चरिंग मिशन की घोषणा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रॉडक्ट बनाने का मौका देना है। इससे न केवल देश में लाखों लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय को भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय कहा और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोत्तरी होगी। श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में ऑटोमोबाइल और फुटवियर इंडस्ट्रीज में उत्पादन और निर्यात ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और ये सेक्टर बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। पहली बार खादी और ग्राम उद्योग के उत्पादों ने एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर पार किया है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं।

अभी कुछ ही दिन पहले अंतर्देशीय जल परिवहन में भी देश की एक और उपलब्धि सामने आई है। वर्ष 2014 से पहले हमारे देश में एक साल में अंतर्देशीय जल परिवहन के द्वारा करीब 180 लाख टन कार्गो मूवमेंट ही किया जाता था, जबकि इस साल इसके द्वारा कार्गो मूवमेंट 1450 लाख टन से भी ज्यादा हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को ये सफलता इसलिए मिली है, क्योंकि भारत ने इस दिशा में लगातार नीतियां बनाई हैं। पहले देश में नेशनल वॉटरवेज की संख्या भी सिर्फ पांच थी, जो कि अब बढ़कर 110 के पार हो गई है। पहले इन वॉटरवेज की ऑपरेशनल लंबाई 2700 किलोमीटर के आसपास थी, जो अब बढ़कर करीब-करीब पांच हजार किलोमीटर हो गई है। इन सभी उपलब्धियों की वजह से देश में युवाओं के लिए नए-नए अवसर बन रहे हैं।

अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ कर बोले श्री अमित शाह

पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही होगी

सहकार उदय टीम

सीमा सुरक्षा के इतिहास में 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम स्वर्णिम अक्षरों मे लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) वापिस लेने और आतंकवाद के खात्मे के लिए ही होगी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु का पानी और खून एकसाथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद एकसाथ नहीं चल सकते। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास के मौके पर दोहराया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने भारत को 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने का संकल्प लिया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास की एक मजबूत नींव रखी है और इसके साथ ही देश की सुरक्षा, सेनाओं की सुसज्जता और सीमाओं की रक्षा का भी एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि जब भी देश और सरहदों को सुरक्षित रखने का इतिहास लिखा जायेगा, तब ऑपरेशन सिंदूर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

श्री शाह ने कहा कि यहां 1550 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्य हो रहे हैं, जिनमें से 31 लोकार्पण, 60 शिलान्यास और तीन परिसरों में 1070 से ज्यादा परिवारों को घर देना शामिल है। यहां खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी कई रोजगारोन्मुखी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ मिला है। पल्लव ओवरब्रिज का उद्घाटन होने से इससे होकर डेढ़ लाख वाहन बिना किसी सिग्नल और ट्रैफिक अवरोध के अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि पूरे अहमदाबाद में करोड़ों रुपए के खर्च से जल वितरण केंद्र, बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन, 237 करोड़ का साबरमती- चांदखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज, 131 करोड़ के खर्च से साबरमती नदी पर डेकोरेटिव लाइटिंग थीम और 38 करोड़ के खर्च से कई ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्टस एक्टिविटीज के कार्य संपन्न हुए हैं। इसी तरह पूर्व और पश्चिम में भी 38 करोड़ के पीएम आवास योजना घरों के निर्माण, जल विद्युत स्टेशन, पंचवटी जंक्शन पर फ्लाईओवर, वटवा में 44 करोड़ का जल वितरण स्टेशन, निकोल में 38 करोड का जल वितरण स्टेशन और वासणा में 34 करोड़ का जल वितरण स्टेशन शुरू हुआ है। श्री शाह ने कहा कि यहां इलेक्ट्रॉनिक पॉटर व्हील, सिलाई मशीन, लेदर टूल किट, कच्ची घानी के तेल की मशीन, अगरबत्ती बनाने की ऑटोमैटिक मशीन के माध्यम से करीब 1000 से ज्यादा लाभार्थियों को रोजगार संबंधी सुविधा देने का कार्य खादी ग्रामोद्योग ने किया है। ■

देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और इसमें दिखे नए भारत की शक्ति को सम्मान देने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। गुजरात में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह नया भारत अपनी धरती और अपने लोगों को नुकसान पहुँचाने वालों को पाताल से भी ढूँढ कर सजा देगा।

सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए तैयार

सहकार उदय टीम

भारत में खेल अब एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित हो रहे हैं। खेल के लिए एथलीटों का जुनून और उत्कृष्टता की निरंतर खोज राष्ट्र को गौरवान्वित करती है। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन के दौरान साझा किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत में ओलंपिक की मेजबानी करना देशवासियों का लंबे समय से संजोया गया सपना है और भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने का प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर के खिलाड़ी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, 'भारत की खेल संस्कृति बढ़ने के साथ ही वैश्विक मंच पर देश की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी।'

प्रधानमंत्री ने भारत के खेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर सरकार के फोकस को दोहराते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में खेल बजट तीन गुना से अधिक बढ़कर इस वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र संचालित हैं, जिनमें बिहार में तीन दर्जन से अधिक केंद्र हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजगीर में खेलो

- देश में खेल अवसंरचना को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही सरकार
- भारत की खेल संस्कृति बढ़ने के साथ ही वैश्विक मंच पर देश की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी
- अच्छे खिलाड़ियों के साथ-साथ उत्कृष्ट खेल पेशेवर तैयार करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया

इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। श्री मोदी ने पटना-गया राजमार्ग के साथ एक खेल शहर के निर्माण और बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा

10

वर्षों में तीन गुना की वृद्धि के साथ देश का खेल बजट लगभग

4,000

करोड़ रुपए का हुआ

खेल से खुल रही हैं विकास की नई राह

कि राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर के खेलों की बारीकियों को समझने और मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन खेलों के दौरान पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय सहित बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें छह हजार से अधिक युवा एथलीट अपने सपनों और आकांक्षाओं के साथ इन खेलों में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि पूरे वर्ष देश भर में खेलो इंडिया के अंतर्गत विभिन्न खेल आयोजन, जैसे- विश्वविद्यालय खेल, युवा खेल, शीतकालीन खेल और पैरा खेल कई स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। इन प्रतियोगिताओं से एथलीटों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी प्रतिभा निखरती है। आईपीएल क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी के इतनी कम उम्र में क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैभव की कड़ी मेहनत ने उनकी प्रतिभा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर कौशल सुधार और खेल में निखार लाने के लिए अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रेरणा दी।

स्कूल स्तर पर हो रही खेल प्रतिभाओं की पहचान

प्रधानमंत्री ने स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के सरकार के ध्यान को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टीओपी) योजना जैसी पहलों ने एक मजबूत खेल इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान दिया है, जिससे बिहार और देश के बाकी हिस्सों में हजारों एथलीट लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने एथलीटों को विभिन्न खेलों की जानकारी प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने भारत की समृद्ध खेल विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए गतका, कलारीपयट्ठ, खो-खो, मल्लखंब और योगासन जैसे पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों को सम्मिलित किया है। श्री मोदी ने नए और उभरते खेलों में भारतीय एथलीटों की बढ़ती उपस्थिति और वुशु, सेपक टाकरा, पेनकैक सिलाट, लॉन बॉल्स और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में हाल के सराहनीय प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन ऐतिहासिक क्षणों को याद किया, जब वर्ष 2022 में भारत की महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स में पदक हासिल किया। इससे भारत में इस खेल को वैश्विक पहचान मिली। ■

श्री मोदी ने कहा, 'खेल की दुनिया और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था खेल के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। खेल युवा व्यक्तियों के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खोल रहे हैं।' फिजियोथेरेपी, डेटा एनालिटिक्स, खेल प्रौद्योगिकी, प्रसारण, ई-स्पोर्ट्स और प्रबंधन जैसे विभिन्न उभरते क्षेत्रों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये करियर के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पेशेवर प्रशिक्षक, फिटनेस ट्रेनर, भर्ती एजेंट, इवेंट मैनेजर, खेल वकील और मीडिया विशेषज्ञ के रूप में भूमिकाएं और रोजगार तलाश सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना और मुख्यधारा की शिक्षा में खेलों के एकीकरण जैसी पहलों के साथ खेल उद्यमिता में बढ़ती संभावनाओं को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री ने जीवन के हर पहलू में खेल भावना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल टीम वर्क, सहयोग और दृढ़ता को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने एथलीटों को प्रोत्साहित करते हुए उनसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और ब्रांड एंबेसडर के रूप में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया और उम्मीद जताई कि खेलो इंडिया युवा खेल प्रतिभागियों के बीच खेल भावना और देशभक्ति दोनों को बढ़ाएंगे।

देश भर में

1,000

से अधिक खेलो इंडिया केंद्र

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

गांधीनगर में विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान बोले श्री अमित शाह

देश को हर क्षेत्र में विकसित और सुरक्षित कर रही मोदी सरकार

- भारत की सेनाओं की क्षमता व मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रशंसा कर रहा पूरा विश्व
- आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर बने आतंकी कैंपों को किया ध्वस्त
- पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर उनकी वायु सेना की हमला करने की क्षमता को तहस-नहस कर दिया

सहकार उदय टीम

भारत हर क्षेत्र में विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात की ही तर्ज पर देश का विकास कर रहे हैं। उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में विकसित करने के साथ-साथ सुरक्षित भी किया है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के देशवासियों को दिए अपने वचन को पूरा कर दिखाया है और भारत ने आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर जाकर पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों

को ध्वस्त किया है। श्री शाह ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, संयम और प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की प्रशंसा कर रही है। जो लोग हमें न्यूक्लीयर पावर के नाम पर डराते थे, उन्हें हमारी वायु, जल और थल सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम से पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। श्री शाह ने कहा कि जब तक दुनिया में मिलिटरी ऑपरेशन्स की चर्चा होगी, तब ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं ही हमारी माताओं-बहनों के सम्मान में इस ऑपरेशन का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि सिंदूर का सम्मान भारत का संस्कार है और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया। श्री शाह ने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि गुजरात और भारत माता के सपूत श्री मोदी ने भारत माता के मस्तक को ऊंचा और देश को सुरक्षित किया है।

वर्ष 2014 के बाद तीनों हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले आए दिन आतंकी हमले होते थे और पाकिस्तान से आए आतंकी हमारे जवानों और जनता को मार कर और और बम धमाके करके चले जाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता था। वहीं श्री मोदी के नेतृत्व के दौरान देश में तीन बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें पहला हमला उरी, दूसरा पुलवामा और तीसरा हमला हाल ही में पहलगाम में करने का दुस्साहस पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवादियों ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर हमले का जवाब इतनी ताकत के साथ दिया है कि अब पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि जब उरी में आतंकी हमला हुआ, तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका प्रतीकात्मक जवाब दिया, पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई। लेकिन, पाकिस्तान और आतंकवादी फिर भी नहीं सुधरे और उन्होंने पहलगाम में हमला किया। इस बार सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनियाभर के सुरक्षा विशेषज्ञों को विश्लेषण करने पर ऑपरेशन सिंदूर आश्चर्यचकित कर रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैय्यबा के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाकर लिया।

100 से अधिक आतंकी और 9 पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त

श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे नागरिकों-पर्यटकों का धर्म पूछकर, उनके परिवारों और बच्चों के सामने उनकी कायराना और निशृंस हत्या की। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब अपने संस्कार के हिसाब से दिया। श्री शाह ने कहा कि भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैय्यबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और भारत की वीर सेनाओं ने नौ ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया, जहां आतंकी तैयार और प्रशिक्षित किए जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के कई स्थानों और पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों को जवाब दिया है। कई अंतरराष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना और कैंपों में छिपे आतंकियों को हमारे बमों के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदश दिया है कि अगर भारत की जनता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार और आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दोगुने जोश के साथ दिया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आठ मई को हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर और भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। लेकिन, श्री मोदी के सेवाकाल में समर्थ बने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारत की भूमि पर नहीं गिरने दिया और पाकिस्तान किसी भी प्रकार भारत को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक दुर्दांत आतंकियों को समाप्त करने के बाद भारत के वीर जवानों ने नौ मई को पाकिस्तान के कई एयरबेस और 15 जगहों पर हमला करके उनकी वायु सेना की क्षमता को तहस नहस कर दिया। श्री शाह ने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की सेनाओं के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर देख रही है।■

गांधीनगर को 708 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात

श्री शाह ने नगर निगम और जीयूडीए द्वारा कराए गए 708 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और वावोल व पेथापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले नए अंडरब्रिज का उद्घाटन भी किया। श्री शाह ने कोलवाड़ा गांव में निगम और डाक विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कोलावाड़ा अमृत झील की तीर्थयात्रा भी की। उन्होंने गांधीनगर नगर निगम के अंतर्गत 78 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 575.43 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इनमें उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 168 करोड़ रुपए की लागत की 15 परियोजनाएं, दक्षिण क्षेत्र में 321.50 करोड़ रुपए की लागत की 22 परियोजनाएं तथा दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए 85.26 करोड़ रुपए की लागत की 8 परियोजनाएं शुरू की गईं। मुख्य परियोजना में सेक्टर-22 पंचदेव मंदिर से सेक्टर-21 तक 16.46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला अंडरब्रिज और कोलवाड़ा में 11.52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला तालाब भी शामिल है।

International Year of Cooperatives 2025 Cooperatives Build a Better World

मेहसाणा में आयोजित एक समारोह में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

गरीब के घर के पास ही सुलभ होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के समग्र विकास के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2014 से देश के 140 करोड़ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया है। इन तथ्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में श्री के के पटेल और श्रीमती मधुबेन पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर दोहराया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, हर घर जल, हर घर में शौचालय और मिशन इन्द्रधनुष आदि व्यापक योजनाओं के जरिए देशवासियों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि हर बच्चे के टीकाकरण, पोषण अभियान और आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के आरोग्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर गरीब को उसके घर के पास ही उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2018 में

- एक दशक में स्वास्थ्य बजट 37 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपए हुआ
- नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत व्यापक अभियान चला रही सरकार
- एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हुई, जबकि मेडिकल कॉलेज 387 से 780 हुए
- 60 लाख नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड से पांच लाख तक का निशुल्क इलाज की सुविधा
- पिछले 10 वर्षों में जन औषधि योजना से नागरिकों को मिली 25 हजार करोड़ रुपए की सस्ती दवाई

देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की। इस योजना के लागू होने के बाद 60 लाख जरूरतमंद नागरिकों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है, जिसके जरिए

स्वास्थ्य ढांचा हुआ मजबूत, बढ़ी टेली-मेडिसिन की सुविधा

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश का स्वास्थ्य बजट 37 हजार करोड़ रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में एक लाख 37 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में वृद्धि करके सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा किया, आयुष्मान भारत योजना शुरू की और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 730 बड़े पब्लिक हेल्थ इंस्टॉलेशन और तहसील स्तर के 3,382 पब्लिक हेल्थ इंस्टॉलेशन बनाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में सिर्फ सात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) थे, जो अब 23 हो चुके हैं। इस दौरान देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर दोगुने से अधिक 780 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए एमबीबीएस की सीटों की संख्या को भी दो गुना से अधिक करते हुए उसे 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख 18 हजार कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि इस दौरान सरकार ने 'मास्टर इन मेडिसिन/सर्जरी' की सीटों की संख्या भी 31 हजार से बढ़ाकर 74 हजार कर दिया है, जिससे देश में आबादी के हिसाब से सुयोग्य डाक्टरों की जरूरत पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम के साथ टेली-मेडिसिन सुविधा बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को प्रभावी बनाकर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नागरिकों को 25 हजार करोड़ रुपए की सस्ती दवाई सुलभ कराई है।

वे पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है और इसके लिए लाभार्थी की इनकम की कोई तय सीमा भी नहीं है। श्री शाह ने कहा कि अब हर अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने राज्य के अस्पतालों का आह्वान किया कि वे अपने अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के मानकों के अनुरूप बनाएं, ताकि आम जन और अस्पताल प्रबंधन दोनों को लाभ हो सके।

श्री शाह ने कहा कि जिस नर्सिंग कॉलेज का उद्‌घाटन हुआ है, वह 3700 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है और इस संस्थान में बीएससी नर्सिंग सहित नर्सिंग संबंधी लगभग सारे पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं। लेक्चर रूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कार्यालय जैसी सुविधाओं से युक्त यह भवन क्षेत्र के युवाओं को सहज व सुलभ चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह नर्सिंग कॉलेज 65 वर्षों से निरंतर नर्सिंग शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। महिला छात्रावास का काम भी प्रगति पर है। कैंसर अस्पताल की स्थापना पर भी जल्द काम शुरू होने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में इस क्षेत्र के लोगों, विशेष रूप से गरीब नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दान से शुरू हुए अस्पताल को चलाने और इसे अत्याधुनिक बनाने की जिम्मेदारी समाज की है। ■

नई दिल्ली में नया ओसीआई पोर्टल जारी कर बोले श्री अमित शाह

प्रवासी भारतीयों को घर लौटने में नहीं होगी कोई असुविधा

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने ओसीआई कार्डधारक मूल नागरिकों को विश्वस्तरीय इमीग्रेशन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व के कई देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भारत आने और यहां प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इन संकल्पों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पोर्टल लॉच करते हुए व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों और नए उपयोगकताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। नया ओसीआई पोर्टल मौजूदा URL: https://ociservices.gov.in पर उपलब्ध है।

श्री शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओसीआई कार्डधारकों से मिले फीडबैक को देखते हुए मौजूदा कमियों को दूर करने और उपयोगकताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया ओसीआई पोर्टल विकसित किया गया है। नए ओसीआई सेवा पोर्टल में कई प्रयोगकताओं के अनुकूल सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसके कार्यात्मक विशेषताओं में पंजीकरण फॉर्म में उपयोगकर्ता प्रोफाइल विवरण का स्वतः भर जाना, पूर्ण व आंशिक रूप से भरे हुए आवेदनों को प्रदर्शित करने वाला डैशबोर्ड, आवेदन करने वालों के लिए एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे, आवेदन के प्रकार के आधार पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का वर्गीकरण और अंतिम रूप से जमा करने से पहले आवेदन में आवेदक के लिए किसी भी स्तर पर संशोधन करने का विकल्प जैसी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। पोर्टल में एकीकृत रूप में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अंतिम रूप से आवेदन फाइल करने से पहले जानकारी को सत्यापित करने के लिए आवेदक को रिमांडर, चयनित आवेदन प्रकार के आधार पर पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों का प्रदर्शन के साथ ही आवेदक की तस्वीरों व हस्ताक्षरों को अपलोड करने के लिए 'इन-बिल्ट इमेज क्रॉपिंग टूल' भी दिए गए हैं। नए ओसीआई पोर्टल में अनेक तकनीकी विशेषताएं भी हैं, जिनमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी रेडहैट 9 पर कई वेब सर्वरों और लोड बैलेंसर के साथ उच्च उपलब्धता का होना और सॉफ्टवेयर व प्लेटफॉर्म अपग्रेड आदि शामिल हैं। इसमें उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करते हुए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रबंध किया गया है। इसमें डेटा भंडारण और पहुंच को केंद्रीकृत व अनुकूलित करते हुए सभी उपकरणों के लिए अनुकूल बनाया गया है और यह मोबाइल अनुकूल भी है। इसके अलावा यह पोर्टल साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है।

➲ ओवरसीज सिटीजन के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओसीआई पोर्टल का किया शुभारंभ

देश में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक योजना की शुरूआत वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से हुई थी। इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वे 26 जनवरी,1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तारीख को नागरिक बनने योग्य हों। लेकिन, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं, उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या वहां रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं। वर्तमान में कार्यरत ओसीआई सेवा पोर्टल को वर्ष 2013 में विकसित किया गया था जो अब विदेशों में 180 से अधिक भारतीय मिशनों के साथ-साथ 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों में काम कर रहा है और प्रतिदिन लगभग 2,000 आवेदनों की प्रोसेसिंग करता है। ■

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली इंजन हैं सहकारी समितियां

सहकार उदय टीम

- कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात में मदद देता है एनसीडीसी
- एनसीडीसी के गतिशील विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी समितियों को मिल रही मजबूती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार सहकारिता के माध्यम से ठोस रणनीतिक स्तर काम कर रही है और इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका है। ऐसे में, एनसीडीसी की प्रगति और रणनीतिक पहलों की समीक्षा के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने एनसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने एनसीडीसी के गतिशील विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि, समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली इंजन के रूप में सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर नए सिरे से जोर दिया। श्री मोहोल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के '*सहकार से समृद्धि*' के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी पहलों से अर्जित हो रही उपलब्धियां राष्ट्रीय विकास के लिए एक उत्प्रेरक बन रही हैं।

देश में सहकारी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एनसीडीसी का सराहनीय योगदान है। सहकारी क्षेत्र के लिए नवीन समाधान प्रदान करने में एनसीडीसी सदैव सक्रिय रही है और यह किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित कर रही है। सभी राज्य और राज्य सहकारी समितियां एनसीडीसी की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। वास्तव में देश में सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी सबसे पसंदीदा वित्तीय संस्थान है जो सहकारी समितियों को बुनियादी ढांचा और व्यापार विकास के साथ ही साथ उनके आर्थिक उत्थान एवं क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करके सहकारी विकास को गति प्रदान करता है। एनसीडीसी कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात आदि के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें बढ़ावा देता है और उनका वित्तपोषण भी करता है। यह निगम ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं सिंचाई जैसी सेवाओं के लिए भी वित्तपोषण करता है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के सहकारी आंदोलन की एक अलग पहचान बन रही है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि योजनाएं बेहद अहम हैं। एनसीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहकारी विकास के लिए कुल 60,618.47 करोड़ रुपए की राशि वितरित की और वित्तीय सहायता के वितरण में 48 प्रतिशत की वृद्धि की। एनसीडीसी का वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लगभग एक लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी एनसीडीसी ने करीब 66 हजार करोड़ रुपए वितरित किए हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए यह अब अपेक्षाकृत कम दरों पर अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए दीर्घकालिक ऋण वितरित करने में सक्षम होगी। निगम ने गहरे समुद्र के ट्रॉलरों के वित्तपोषण का कार्य भी अपने हाथ में लिया है। ■

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की सफलता के बाद

इफको ने उतारा नैनो जिंक और नैनो कॉपर

- प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार कर रहे इफको के विकास के आंकड़े
- वित्त वर्ष 2024-25 में इफको का शानदार प्रदर्शन, नैनो उर्वरकों की बिक्री 47 प्रतिशत बढ़ी

सहकार उदय टीम

नैनो उर्वरकों को किसानों की ओर से मिल रही बेहतर प्रतिक्रिया से विश्व की नंबर एक सहकारी संस्था इफको उत्साहित है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की सफलता के बाद अब इफको ने नैनो जिंक और नैनो कॉपर को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिया है। जल्द ही नैनो एनपीके को भी लॉन्च किया जाएगा। इफको की 54वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) की बैठक में देशभर से आए किसानों और सहकार बंधुओं ने भी नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता बढ़ने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने की कहानी बयां की।

नैनो उर्वरकों की बिक्री में आए जोरदार उछाल भी इनकी सफलता की कहानी कह रहे हैं। इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी और प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की बिक्री में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान नैनो उर्वरकों की 365.09 लाख बोतलें बेची गईं, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2023-2024) में 248.95 लाख बोतलें बेची गई थीं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बेची गई बोतलों में से 268 लाख बोतलें नैनो यूरिया प्लस (लिक्विड) और 97 लाख बोतलें नैनो डीएपी (लिक्विड) की बेची गईं। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में नैनो यूरिया प्लस (लिक्विड) की बिक्री 31 प्रतिशत और नैनो डीएपी (लिक्विड) की बिक्री 118 प्रतिशत अधिक है। यह बिक्री मात्रा 12 लाख टन पारंपरिक यूरिया और 4.85 लाख टन पारंपरिक डीएपी के बराबर है। इस वित्त वर्ष में इफको ने 3,811 करोड़ रुपए का टैक्स पूर्व लाभ कमाया और 41,244 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया।

श्री दिलीप संघाणी ने कहा कि यह देश के पूरे सहकारी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि इफको के शानदार विकास के आंकड़े 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार कर रहे हैं। किसानों की यह सहकारी समिति लगातार तीन वित्त वर्ष से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दर्ज कर रही है। इफको ने अपने सदस्यों को चुकता शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत का लाभांश दिया है। पिछले 23 वर्षों से लगातार सदस्यों को इतना लाभांश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के समर्थन से नैनो उर्वरक इफको के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। व्यापक जागरूकता अभियान और अनुसंधान ने किसानों के बीच इनकी स्वीकृति बढ़ाने में मदद की है।

इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने बताया कि इफको मिट्टी में मूल खुराक के रूप में प्रयोग के लिए दानेदार

रूप में नैनो एनपीके उर्वरक जल्द लॉन्च करेगा। नैनो एनपीके उर्वरक मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर से समृद्ध है जो फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करेगा। लिक्विड नैनो यूरिया प्लस और लिक्विड नैनो डीएपी के साथ यह मिट्टी से पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को खत्म कर सकता है। यह प्राथमिक पोषक तत्वों की उच्च उपयोग दक्षता के साथ संतुलित पोषण को और बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए इफको ने 100 एमएल की बोतल में नैनो जिंक (लिक्विड) और नैनो कॉपर (लिक्विड) भी किसानों के लिए उपलब्ध करवा दिया है। इसकी कीमत 200 रुपए प्रति बोतल रखी गई है।

डॉ. अवस्थी ने बताया कि इफको किसानों को नैनो उर्वरकों के लाभों के प्रति जागरूक कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से इफको देश की कृषि और खाद्य व्यवस्था में बदलाव ला रही है। नैनो उर्वरकों को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। अमेरिका, ब्राजील, केन्या स्लोवेनिया, मॉरीशस, जाम्बिया, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्राजील में इफको एक नैनो उर्वरक प्लांट भी लगा रही है जिसके लिए ब्राजील सरकार ने जमीन मुफ्त में देने के अलावा टैक्स छूट और अन्य बुनियादी

3,811
करोड़ रुपए का हुआ टैक्स पूर्व लाभ

सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इफको ने 40 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। इसके अलावा स्वदेशी आविष्कारों के साथ 'देसी' बीजों को संरक्षित करने के लिए इफको अपने कलोल प्लांट में एक अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केंद्र भी बना रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में इस केंद्र का शिलान्यास किया था।

54वीं वार्षिक आम सभा में इफको ने दो प्रतिष्ठित सहकारी समितियों के शख्सियतों को वर्ष 2023-24 के लिए 'इफको सहकारिता रत्न पुरस्कार' और 'इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार' से सम्मानित किया। गुजरात के महुवा प्रदेश सहकारी चीनी उद्योग मंडली लिमिटेड के संस्थापक श्री मानसिंहभाई कल्याणजीभाई पटेल को 'इफको सहकारिता रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने प्रयासों से सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सहकारी समितियों के बीच जमीनी स्तर पर काम किया है। हरियाणा के श्री अमरीक सिंह को 'इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। कृषि क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के

41,244
करोड़ रुपए का रहा है टर्नओवर

लिए उन्हें पहले भी हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

डॉ. अवस्थी के अनुसार, इफको ने फसल उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नैनो उर्वरकों में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जुलाई 2024 में देशभर में 'मॉडल नैनो गांव और क्लस्टर परियोजना' की शुरूआत की गई, जिसमें 203 गांव क्लस्टरों (प्रत्येक 2,000 एकड़) का चयन किया गया। अब तक 90,000 से अधिक किसान नैनो विलेज पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिन्होंने नैनो उर्वरकों का उपयोग किया। उनकी 5 लाख एकड़ भूमि में से 72,000 एकड़ में कृषि ड्रोन से छिड़काव किया गया। इस पहल से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 28.73 प्रतिशत की कमी आई और फसल उत्पादन में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

35,600 से अधिक सहकारी संस्थाओं और देश-विदेश में 10 प्लांट के नेटवर्क के साथ इफको भारत की नंबर एक फर्टिलाइजर उत्पादक है, जो देशभर में 5 करोड़ से अधिक किसानों को सेवा प्रदान करती है।■

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

बिहार के सीमांचल में इफको नैनो फर्टिलाइजर और ड्रोन तकनीक के नवाचार का असर

मखाना की खेती से समृद्ध हो रहे किसान

सुरुचि कुमारी

बिहार सांस्कृतिक और कृषि संपदा से भरपूर भूमि है और मखाना इसका सबसे बेशकीमती खजाना है। खास तौर पर मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला मिथिला मखाना अपनी पौष्टिकता, औषधीय महत्व और आर्थिक महत्व के कारण न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर मखाना एक पौष्टिक सुपरफूड है और किसानों की आय के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में यह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार भी है। प्रदेश में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी जिले मखाना की खेती के प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में अकेले कटिहार में 6,840 हेक्टेयर और पूर्णिया में 6,550 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती होती है। मखाना की बढ़ती मांग ने किसानों को अधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए नवीन खेती तकनीकों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है।

इस संदर्भ में पूर्णिया जिले के पूर्वी ब्लॉक के कवैया गांव में मखाना किसानों ने 2024 में एक ऐतिहासिक पहल की और पहली बार मखाना की खेती में ड्रोन तकनीक के जरिए इफको के नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का छिड़काव किया गया। इसके आशाजनक परिणाम मिले और पत्तियों की बढ़त में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और सड़न रोगों में उल्लेखनीय कमी आई। यह नवाचार किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ और इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में फसल की उपज में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस शुरूआत का व्यापक असर हुआ है और किसानों में नैनों उर्वरकों की लोकप्रियता बढ़ गई है। वर्तमान फसल वर्ष 2025 में नीरज कुमार नामक किसान ने 35 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती की है और इफको के नैनो उर्वरकों का उपयोग करके दो दौर का छिड़काव किया है। पत्ती विकास के चरण के दौरान और फिर फूल आने से समय से लेकर फूल आने के शुरूआती चरण के दौरान नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग मखाना के लिए बहुत फलदायी साबित हुआ है।

चूंकि, मखाना एक जलीय फसल है और इसकी जड़ें मिट्टी से सीमित पोषक तत्वों को ही अवशोषित करती हैं। इसलिए पत्तियों के माध्यम से इसे पोषण प्रदान करना एक गेम-चेंजर के रूप में उभरा है। इस दिशा में ठोस पहल करते हुए इफको ने पिछले वर्ष 2024 में पूर्णिया जिले में 780 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ड्रोन से छिड़काव किया। वर्ष 2025 के शुरूआती महीनों, खासकर अप्रैल-मई में 410 एकड़ मखाना क्षेत्र में छिड़काव किया गया और यह क्षेत्र दिन-प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। सीमांचल, कोसी और मिथिला क्षेत्रों के किसानों के बीच इस परिवर्तनकारी नैनो तकनीक को अपनाने के लिए किसानों में उत्साह बढ़ा है। कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया के मखाना वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार के अनुसार, 'इफको नैनो डीएपी मखाना फसलों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। केवल 5 मिली प्रति लीटर के साथ यह प्रभावी फॉस्फेट वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इफको नैनो यूरिया प्लस (3 मिली/लीटर), सागरिका और नीम तेल (5 मिली/लीटर) का संयोजन मखाना के बीजों को अधिक पौष्टिक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।'

इस नवाचार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ड्रोन तकनीक है। ड्रोन न केवल समय और श्रम बचाते हैं, बल्कि एक समान और सटीक छिड़काव भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे लागत कम होती है। यह टिकाऊ, लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल कृषि की दिशा में एक साहसिक कदम है। इफको के नैनो उर्वरक और ड्रोन तकनीक बिहार में मखाना की खेती में क्रांति ला रहे हैं। सीमांचल में मखाना की खेती बढ़ रही है और एक नई उम्मीद के साथ नए विज्ञान और कृषि नवाचार को महत्व मिल रहा है। यह बदलाव न केवल कृषि को नया रूप दे रहा है, बल्कि किसानों के भविष्य को भी सशक्त बना रहा है। इस क्रांति के जरिए पूरे बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल और असम में मखाना की खेती के विस्तार की उम्मीदें जगी हैं, जहां यह फसल पहले से ही उगाई जाती है और अब विकास की अपार संभावनाएं बलवती हो रही हैं। इसतरह, इफको नैनो उर्वरकों और ड्रोन तकनीक के जरिए विस्तार के माध्यम से मखाना की खेती को वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया जा सकता है।' ■

-लेखिका इफको के मार्केटिंग विभाग में कार्यरत है

राष्ट्रीय-आर्थिक विकास में सहकारिता की अहम भूमिका

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के '*सहकार से समृद्धि*' के संकल्प के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन अभूतपूर्व गति से विकास और विस्तार कर रहा है। इस दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान (एनएईपी) में कृषि और ग्रामीण विकास में उच्च तकनीक और नए युग की तकनीकों को अपनाने की पहल की गई। आईसीएआर-एनआईएईपी और विश्व सहयोग आर्थिक मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस उच्चस्तरीय राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में 'सहकारी वस्तु एवं आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से सहकारी आर्थिक ढांचे' पर विस्तृत विचार-मंथन किया गया, जिसमें भारत के आर्थिक और सामाजिक नीति परिदृश्य को आकार देने और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समावेशी विकास, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए मार्ग तैयार करने में सहकारी संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की गई। इसमें सहकारी क्षेत्रों को भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख वाहक के रूप में विकसित करने की संभावनाओं और रणनीतियों पर गहन विमर्श किया गया।

➲ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में देश भर के सहकारी क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, नीति निमार्ताओं और पेशेवरों ने की भागीदारी

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की सफलता और समृद्धि के लिए उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए प्रशिक्षण, सहयोग और परियोजनाओं के रूप में ठोस तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे सहकारी ढांचे के माध्यम से देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को सार्थक संवाद और सहयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास, सामाजिक समानता और समावेशी रणनीतियों को बढ़ावा देने में सहकारी आंदोलन की भूमिका की सराहना की और इसे भारत की सहकारी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का एक सराहनीय प्रयास बताया। इस मौके पर 'इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड' (इफको) के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से नैनो उर्वरक देश के ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इस राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन में देशभर से सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, नीति-निमार्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया। भारत की आर्थिक प्रगति में सहकारिता की भूमिका को लेकर विशेषज्ञों ने एक स्वर में मजबूती से यह स्वीकार किया किया कि यदि सहकारी ढांचे को मजबूती दी जाए, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

आयोजन के दौरान तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डॉ. मल्लिका कुमार को सहकारी शिक्षा के प्रति उनकी गहन विशेषज्ञता और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ-साथ एक समतापूर्ण, ज्ञान-संचालित समाज के निर्माण के उनके प्रयासों के लिए रोमाशा पुरस्कार 2025 मिला। सुश्री कामना झा को ग्रामीण विकास में उनकी अभिनव और समावेशी रणनीतियों के लिए 'लक्ष्मी सहगल ग्लोबल अवार्ड 2025' से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में, 'रिवर्स माइग्रेशन' पहल ने ग्रामीण आजीविका को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. उमाकांत दास को सार्वजनिक नीति, सामाजिक समानता और ग्रामीण उन्नति के प्रति उनके आजीवन समर्पण के सम्मान में 'एलवीएस पब्लिक पॉलिसी 2025 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आईसीएआर-एनएईपी के निदेशक डॉ. पी. एस. बिरथल, इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार, निदेशक प्रहलाद सिंह, जगदीप सिंह नकई, नीति आयोग के कमल त्रिपाठी, एमएसपी समिति के सदस्य श्री विनोद आनंद और इरमा के निदेशक डॉ. उमाकांत दास और प्रोफेसर डॉ. मल्लिका कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की। ■

जैविक और आत्मनिर्भर कृषि के लिए प्रेरित कर रही गौग्राम जनजागरण यात्रा

सहकार उदय टीम

- शीर्ष सहकारी संस्था इफको के सहयोग से 24 गांवों के 30,000 से अधिक किसानों तक पहुंची गौग्राम जनजागरण यात्रा 2025
- खेती में गायों के महत्व का एहसास कराना ही इस अभियान का उद्देश्य है
- नैनो उर्वरकों और जैव अपघटकों के उपयोग सहित स्थायी प्रथाओं के बारे में किसानों को किया जा रहा शिक्षित
- ग्रामीण किसानों को रसायन मुक्त और लाभदायक खेती के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण

भारत की कृषि व्यवस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है। जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन, पिछले दशकों में दूध न देने पर गायों को उपेक्षित करने व उन्हें बेच देने की सोच समाज में बढ़ती गई। लोगों की इस मनोदशा को सुधारने और गायों के खोए हुए मूल्य को बहाल करके ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 'गौग्राम जनजागरण यात्रा 2025' शुरू की गई है। गौ-आधारित खेती के बारे में जागरूकता फैलाने और आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष सहकारी संस्था इफको ने इसे गौ सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग और भारतीय किसान विकास संघ व क्रांतिनगर गौशाला के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी बनाया है। इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के उद्देश्य से गौ-पालक और डेयरी किसान इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिसे इफको सक्रिय रूप से सुविधाएं मुहैया करा रहा है। यह जन-जागरण यात्रा शुरूआती दौर में ही 24 गांवों के 30,000 से अधिक किसानों तक सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। इस दौरान किसानों को नैनो उर्वरकों और जैव अपघटकों के उपयोग सहित स्थायी प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। गौग्राम जनजागरण यात्रा की पहल, जिसे सहकार भारती और वैदिक प्राकृतिक खेती का भी समर्थन प्राप्त है, सफलतापूर्वक किसानों को जैविक खेती और आत्मनिर्भर कृषि के लिए प्रेरित कर रही है।

किसानों को खेती में गायों के महत्व का एहसास कराना ही इस अभियान का उद्देश्य है। गोपालन केवल दूध उत्पदन के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और गोबर व पंचगव्य जैसे गाय-आधारित अवशेषों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से फसल उगाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह प्राकृतिक उर्वरक, कीट प्रतिरोधी और मिट्टी बढ़ाने वाले के रूप में काम करता हैं। इस अभियान के दौरान ग्रामीण किसानों को पारंपरिक ज्ञान में निहित वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उनका आत्मनिर्भर कृषि के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। यात्रा के दौरान प्राकृतिक खेती के लिए गोमूत्र और गोबर आधारित उत्पादों का उपयोग करने के तरीकों का प्रदर्शन और फसल अवशेषों को प्राकृतिक उर्वरक में बदलने के लिए नैनो यूरिया और बायो डीकंपोजर के लाभों की भी जानकारी साझा की जा रही है, जिससे किसान रसायन मुक्त और लाभदायक खेती के लिए प्रेरित हो सकें।

ग्रामीण जीवन में गौशालाओं की भूमिका को बढ़ावा

गौग्राम जनजागरण यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण जीवन में गौशालाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है। दरअसल, गाय आधारित जैविक खेती की ओर बदलाव नदियों और भूजल में रासायनिक अपवाह को कम करने में मदद करता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है। गोबर की खाद और बायो-डीकंपोजर के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और सूक्ष्मजीव गतिविधियों में सुधार होता है और इससे स्वस्थ फसलें मिलती हैं। जागरूकता फैलाने और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से, यात्रा किसानों को आत्मनिर्भर बनने और प्राकृतिक, जैविक खेती के तरीकों पर लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।■

गांवों में समावेशी विकास को तेज करेगा इफको

सहकार उदय टीम

- एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए इफको ने ग्रामीण मूल्य शृंखला विकास न्यास (एफडीआरवीसी) के साथ मिलाया हाथ
- देश भर में 800 से अधिक एफपीओ और 10 लाख किसानों पर इसका होगा सकारात्मक असर

देश और दुनिया की अग्रणी सहकारी संस्था इफको अपने नवाचारी पहलों एवं अनुसंधानों के माध्यम से भारतीय किसानों की समृद्धि और कृषि व्यवस्था में दूरगामी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपनी उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा किसान-केंद्रित समाधानों के माध्यम से भारतीय कृषि में निरंतर क्रांति ला रहा है। प्रसंस्कृत उर्वरक एवं कृषि-आदान के विनिर्माण व विपणन क्षेत्र में विश्व में अग्रणी इफको ने हाल ही में एक अभिनव पहल करते हुए ग्रामीण मूल्य शृंखला विकास न्यास (एफडीआरवीसी) के साथ एक रणनीतिक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे भारत में नवीन, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदान तक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की पहुंच बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इससे देश के सुदूर भागों तक इफको के नैनो उर्वरकों और विशेष उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी और स्थानीय एफपीओ के माध्यम से किफायती कीमतों पर छोटे किसानों तक विश्व स्तरीय कृषि-आदानों की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसका लाभ देश भर के 800 से अधिक एफपीओ और 10 लाख किसानों को मिलेगा।

इस साझेदारी के माध्यम से इफको एफडीआरवीसी से जुड़े एफपीओ को अभिनव नैनो उर्वरक, जैव-उत्तेजक, विशेष उर्वरक और जैविक आदान जैसे जैव-उर्वरक और जैव-अपघटकों की आपूर्ति करेगा। यह पहल न केवल कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करेगी, बल्कि सामूहिक खेती के माध्यम से टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन का भी समर्थन करेगी। समझौते के तहत, एफडीआरवीसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एफपीओ के अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण समाज के अंतिम लोगों तक किसान शिक्षा और इन आदानों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा। यह साझेदारी एफपीओ की संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने और उन्हें आत्मनिर्भर ग्रामीण उद्यम बनने के लिए तैयार करने में भी मदद करेगी।

इफको और एफडीआरवीसी की यह साझेदारी नवाचार को बढ़ावा देने, आदानों की पहुंच में सुधार लाने और छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच लचीलेपन को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह एफपीओ की संस्थागत क्षमता के निर्माण की दिशा में भी काम करेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर ग्रामीण उद्यमों के रूप में विकसित हो सकें। इससे न केवल छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर संसाधनों के साथ सशक्त बनाया जा सकेगा। यह साझेदारी तकनीकी नवाचार को जमीनी स्तर पर पहुंच के साथ जोड़कर देश के कृषि क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे फसलों की पैदावार में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि और अधिक लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है।

एम. के. मिश्रा

भारत में सतत और नैतिक विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका

वर्तमान दौर में जब उपभोक्ता सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि उनके पीछे की नैतिकता एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं, सतत विकास और नैतिक विपणन बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत में सहकारी समितियां इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और व्यापार करने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियों का मॉडल साझा स्वामित्व और सामूहिक लाभ पर आधारित होता है और यह उन्हें पारंपरिक कंपनियों से अलग पहचान देता है।

सतत विपणन से आशय यह है कि उत्पादों व सेवाओं को इस तरह से बेचा जाए, जिससे पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने जैसे पहलू शामिल हैं। वहीं, नैतिक विपणन का अर्थ है व्यापार में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी। इसमें भ्रामक विज्ञापनों से बचाव, उचित मूल्य निर्धारण, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और नैतिक सोर्सिंग को बढ़ावा देना शामिल है। यह ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसका एक सामान्य उदाहरण है, जो कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहित करता है। इसीतरह, पतंजलि भी एक ब्रांड है जो जैविक व आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण कर किसानों को समर्थन देता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।

भारत में सहकारी समितियां सतत और नैतिक विपणन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-केंद्रित व्यापार दृष्टिकोण पर काम करती हैं। ये समितियां अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सामाजिक कार्यों में व्यय करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही, ये समितियां स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करके उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का काम करती हैं। निष्पक्ष व्यापार और नैतिक सोर्सिंग को बढ़ावा देते हुए सहकारी समितियां किसानों व कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदती हैं। इससे बिचौलियों का शोषण कम होता है और किसानों को उचित मूल्य मिलता है। अमूल इसी तरीके से किसानों से सीधे दूध खरीदकर उन्हें उचित मूल्य लाभ प्रदान करता है।

सहकारी समितियां पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद विकास के जरिए जैविक उत्पादों, बायो-डिग्रेडेबल पैकेजिंग और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर जोर देती हैं। वे जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा देती हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अमूल ने प्लास्टिक पैकेजिंग कम करते हुए दूध और दही के लिए पारंपरिक प्लास्टिक पैकेजिंग के बजाय बायो-डिग्रेडेबल और पुनः प्रयोज्य सामग्रियों का उपयोग बढ़ाया है। इसने प्लास्टिक स्ट्रॉ और चम्मचों की जगह कागज या लकड़ी से बने विकल्पों को अपनाया है, जिससे प्लास्टिक कचरे में कमी आई है।

सहकारी समितियां अपने वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता अपनाते हुए नियमित रूप से अपनी आय-व्यय रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं ताकि उपभोक्ताओं और हितधारकों का विश्वास बना रहे। साथ ही, वे अपने सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करती हैं, जिससे संगठन की स्थिरता और विश्वसनीयता बनी रहती है। इसके अलावा, लाभ-केंद्रित कंपनियों के विपरीत, सहकारी समितियां शिक्षा और जागरूकता अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को सतत उपभोग, निष्पक्ष व्यापार और जिम्मेदार उपभोक्तावाद के प्रति शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्यावरण-अनुकूल एवं नैतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं को खरीदने को प्रेरित करती हैं। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए समितियों के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

भारत में सफल सहकारी विपणन रणनीति को लागू करते हुए अमूल निष्पक्ष डेयरी व्यापार का प्रतीक बन गया है। यह डेयरी किसानों को उचित मूल्य देकर, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाकर और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग अपनाकर सतत व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह, 'सेल्फ इंप्लायड वीमेन्स एशोसिएशन' (सेवा) महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाते हुए महिला श्रमिकों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनने में मदद करता है। इन प्रयासों से सहकारी समितियों की स्थिति बाजार में भी मजबूत हो रही है और उपभोक्ताओं में नैतिक व्यापार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ■

उपनिदेशक, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ

इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी के साथ निदेशक मंडल ने 595वीं बैठक के दौरान एक एजेंडा पारित किया, जिसमें देश के नागरिकों, समुदायों और संगठनों से किसी भी उकसावे का सामना करने के लिए एकजुट रहने और सामूहिक रूप से पूरे देश में शांति, सद्भाव और लचीलापन को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया।

इफको के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. उदयशंकर अवस्थी ने अम्मान, जॉर्डन में जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी (जेपीएमसी) की वार्षिक आम सभा में भागीदारी की, जिसमें जिफको के अध्यक्ष महामहिम प्रोफेसर डॉ. मुहम्मद अल-थानीबत अल-अकरम के साथ अन्य निदेशकों व आम सभा के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।

भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड (आईएफएफडीसी) के बीज प्रसंस्करण इकाई मैगलगंज, जिला लखीमपुर (उप्र) में आयोजित कार्यक्रम में इफको अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने समितियों के माध्यम से किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा दी।

भारतीय कृषि में चार दशकों से अनुकरणीय योगदान कर रहे इफको के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। ऐतिहासिक नवाचारों और सामाजिक हस्तक्षेपों का नेतृत्व कर श्री कुमार ने देश के लाखों किसानों के जीवन में बदलाव में अहम भूमिका निभाई है।

सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोर के नेतृत्व में सहकार भारती के एक प्रतिनिधिमंडल ने इफको के गुरुग्राम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में नैनो उर्वरकों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन यादगार पलों को इफको के पदाधिकारियों के साथ सामुहिक छायाछित्र में भी सजोंया।

गंगा बहुउद्देशीय सभागार जनपद बलिया (यूपी) में नैनो उर्वरक आधारित फसल उत्पादकता वृद्धि विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इफको, निदेशक एवं यूपीपीसीएफ लखनऊ के अध्यक्ष श्री वाल्मीकि त्रिपाठी ने किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रयोग और फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

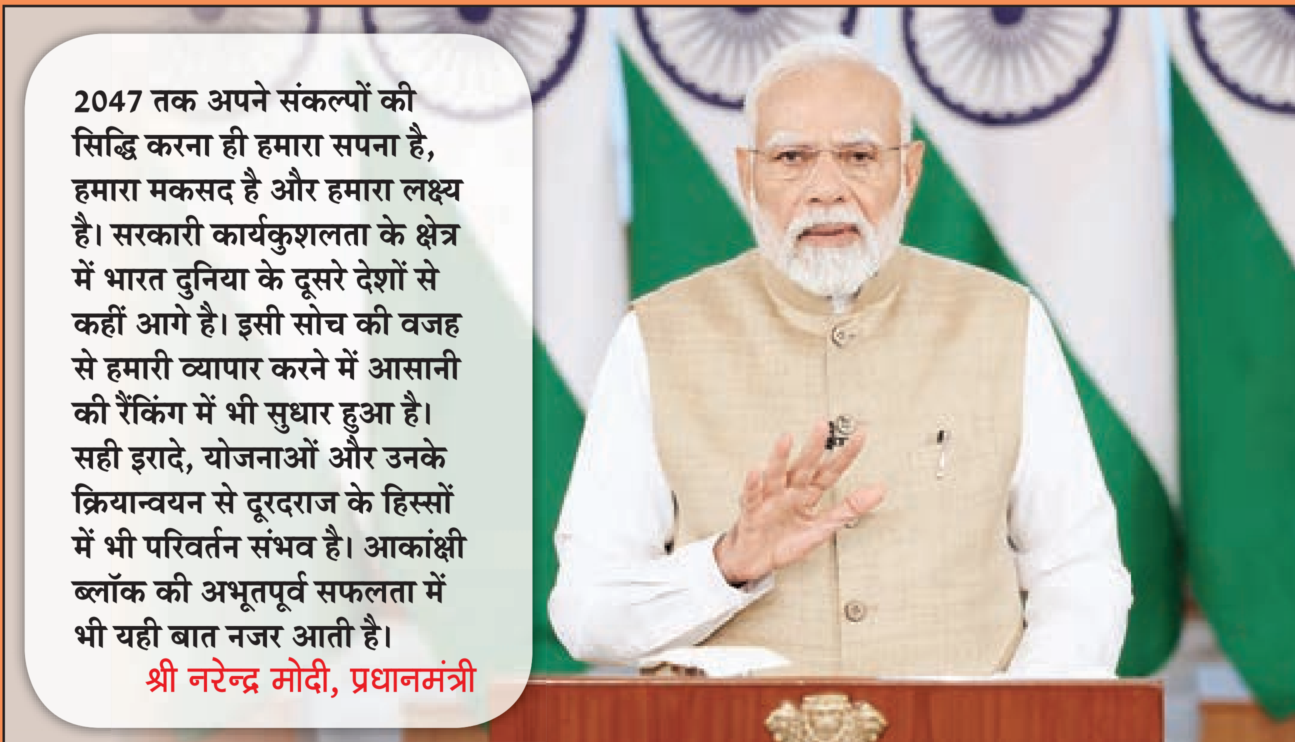

Published on 16th June 2025
" Sahkar Uday"

RNI No. DLHIN/24/A0001
Postal Registration No.: DL(S)-17/3560/2024-26

Posting Date : 16th - 21st June 2025
Posted at : Lodhi Road HO, New Delhi - 110003